यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस संबंध में जांच करायेंगे और इस रैकट को खत्म करने के लिये कोई विशेष कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

MR. SPEAKER: It is too general a question. He may give separate notice of it.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कंट्रोल क्लाथ की मंहगाई के बारे में है। कोर्स क्लाथ की दुकानों में इस लिये बढ़ोतरी हो रही है कि जो कपडा कोआपरेटिव की दुकानो के जरिये उपभोक्ताओ के पास पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंच रहा है। क्या मंत्री महोदय, इसके बारे मे जांच करायेंगे ?

SHRI K. R. GANESH: If he tables a specific question, I will look into it.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जो सगठित मजदूर है उनको तो महगाई भत्ता मिलता है, हालाकि इण्डेक्स नम्बर मे बहुत बेइमानी होती है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू—देश मे 25 प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं, कुछ राज्यो मे जैसे आन्ध्र प्रदेश में 37 प्रतिशत हैं, बिहार में 38 प्रतिशत है, उनके जीवन पर जो असर पडेगा, क्या उनके लिये सरकार कोई सार्वजनिक राशन व्यवस्था या कोई अन्य व्यवस्था चलाने के बारे मे सोच रही है ?

SHRI K. R GANESH: The proposal of having public distribution system which was recommended by the Dharia Committee is under the consideration of Government.

SHORT NOTICE QUESTION

Shortage of stamp papers in Delhi Courts

+

S.N.Q. 13. SHRI SAT PAL KAPUR:
SHRI P. K. DEO:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is acute shortage of stamp papers of small denominations like Re. 1/- Rs. 1.50 and Rs. 2/- with the stamp vendors in the courts of Delhi;

(b) whether on account of that people have to purchase stamp papers either of higher denominations or of small denominations by paying illegally higher prices; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): (a) Yes, Sir.

(b) Delhi Administration has not received any specific complaint regarding charging of illegal prices by the Stemp Vendors. It has, however. issued instructions to Stamp Auditors to exercise strict supervision over the activities of the various Stamp Vendors and make surprise checks of their vends to ensure that they do not take advantage of temporary shortage and indulge in any such mal-practices.

(c) Supplies have been rushed to Delhi from Nasik and the position is expected to normalise in the next few days.

श्री सतपाल कपूर : स्पीकर साहब, इल्लीगल प्राइस तो कोई फिक्स्ड नहीं है, लीगल प्राइस फिक्स्ड है। दिल्ली मे ही नही सारे हिन्दुस्तान मे स्माल-डिनामिनेशन के स्टैम्प पेपर नही मिलते है ? हमे तजुर्बा है कि वे लोग 10 रुपये का कागज 20 रुपये और 30 रुपये में बेचते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सप्लाई कम क्यो होती है वक्त पर क्यो नहीं पहुंचती ?

SHRI K. R. GANESH: As far as the Delhi Administration is concern-

ed, the major problem arose in relation to non-judicial stamp paper of the denomination of Rs. 2. The Delhi Administration had indented to stamp papers of the denomination of Rs. 2 of the order of 3,94,000, but the Nasik ress could, at that point of time, supply only upto 12,000, the reason being that the Press had to divert some of its printing capacity to the printing of Indipex Mindature Sheets required by the P. & T. Board and also for printing N-J stamps for Bangladesh. Also a consignment of 96,000 stamp papers of Rs. 2 denomination despatched from the Nasik Press by good train on 1st March was held up for some reason and reached only on 22 April. In the next few days, steps are being taken to rush supplies to them.

श्री सतपाल कपूर : 3 महीने से सप्लाई नहीं हो रही है—क्या मिनिस्टर साहब या उनके डिपार्टमेंट ने किसी पर कोई रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स की है, किसी आफिसर को कोई सजा दी है, वार्निंग दी है कि आपने अपनी ड्यूटी वक्त पर पूरी नहीं की है ।

दूसरी तजवीज मैं यह देना चाहता हूं कि जब स्टाम्प पेपर न मिले तो क्या सरकार ऐसी किसी तजवीज पर गौर करने को तैयार है कि जिनको स्टाम्प पेपर न मिलता हो, वे अपना पैसा ट्रैजरी में जमा करवा दें और ट्रैजरी की रसीद को वैलिड मानलिया जाय ?

SHRI K. R. GANESH: The Delhi Administration has already issued instructions to the Collector of Stamps, Delhi, who has advised the Treasury Officer, Delhi, to accept printed/cyclostyled/typed unexecuted documents for affixation of special adhesive stamps of the required value on cash payment in the treasury. As an alternative measure, the Delhi Administration have advised the public to execute documents on palin watermarked paper and thereafter present the same for endorsement to the Collector in accordance with the provisions of sec. 41 of the Indian Stamp Act 1899 on payment of the required duty in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi.

श्री सतपाल कपूर : मैंने रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करने की बात भी पूछी थी ? मेरी तजबीज तो उन्होंने मान ली है—यह अच्छी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : रेस्पोंसिबिलिटी बड़ी मुश्किल से फिक्स होती है ।

SHRI B. V. NAIK: Sir, I am very glad that the hon. Minister of State in the Ministry of Finance at the Centre has chosen to answer on a subject which is exclusively within the States' preserve. In spite of that, to the extent to which it is a Centrally-administered one, it comes in List No. 2 I have looked into the Constitution. (*Interruption*) This is a very valid point. Now, all over the country, these denominations, particularly the lowner denomination of stamp-papers, are in short supply. So, will any sort of survey be kindly undertaken by the Ministry of Finance all over the country and all over the States so as to see that the hardship of the stamp-vendors as well as that of stamp-users in this country is removed?

SHRI K. R. GANESH: It is a good suggestion for action.

MR. SPEAKER: It is a very good suggestion.

श्री आर० बी० बडे : मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि मेरी स्टेट में जहां जहां स्टाम्प पेपर कम पड़ता है प्राय: कचहरियों में 1 रुपये का, डेढ़ रुपये का, दो रुपये का पेपर स्टाम्प कम पड़ता है, तो वहां एक रजिस्टर रख दिया जाता है जिसमें रुपया

जमा कर दिया जाता है और वह ट्रेजरी को भेज दिया जाता है—सरकार ऐसी व्यवस्था यहां पर क्यों नहीं करती ?

SHRI K. R. GANESH: I have information only about Delhi.

श्री आर० वी० बड़े : इसी लिये मैं पूछ रहा हूं कि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। पैसा कचहरी के रजिस्टर में जमा हो जाय और बाद में उस पैसे को ट्रैजरी में भेज दिया जाय ।

MR. SPEAKER: He is giving you some suggestions.

SHRI K. R. GANESH: Yes, Sir.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह क्या जवाब दिया है सरकार स्टम्प पेपर भी नहीं छाप सकती, कोई मुफ्त नहीं देती है, पैसे के बदले उसको बेचती है । यह सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि समय पर स्टैम्प पेपर नहीं छाप कर दे सकती । इन्होंने कोई कठिनाई भी नहीं बताई है—कागज नहीं है या प्रैस में काम ज्यादा है —क्या वजह है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके आने से पहले वजह बताई थी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो शुरू से यहीं हूं इन्होंने जो करण बतलाया है, वह ऐसा कारण नहीं है कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन यह चिन्ता की बात है कि लोगों को पैसे के बदले स्टैम्प पेपर भी नहीं मिलता ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने पहले प्रश्न के जवाब में बतलाया था, बहुत लम्बा-चौड़ा जवाब दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर सरकार को कठिनाई हो तो हम अपने प्रैस में छाप कर दे सकते हैं ।

श्री सतपाल कपूर : ये प्रैस भी चलाना चाहते हैं, व्यापार भी अपना चलाना चाहते हैं, नोट छापने का काम भी इनको दे दो ।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्टैम्प-पेपर की शार्टिज का कारण यह है कि कुछ स्टैम्प वेन्डर लोग जानबूझकर ब्लैक करने की नीयत से दबा देते हैं । मुझे ऐसा अनुभव है, इसलिये कह रहा हूं। मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट कोर्ट में गया था, ये लोग वहां से गायब हो जाते हैं, चार वैन्डर्ज है, उनमें से एक मौजूद था, तीन चले गये थे। मैंने तो ब्लैक का पैसा नहीं दिया लेकिन इसके लिये मुझे डेढ़ घंटा समय लगा। क्या वैन्डर्ज के रिवाज को खत्म करके डिपार्टमेन्टली बिक्री से बेचने की व्यवस्था करेंगे, जिस तरह से पोस्ट आफिस में पोस्टेज स्टैम्प बिकते हैं और उनमें कोई ब्लैक नहीं होती है ।

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Order, please. Let him reply.

SHRI K. R. GANESH: When there is shortage of certain denominations of these notes which have not come from the Nasik Press, it is inevitable that the vendors might be making some profit and might also be doing some illegal transactions, and that is why, in reply to the question raised, the Delhi Administration have asked their staff to be vigilant as far as these vendors are concerned.

SHRI BHOGENDRA JHA: Why not do away with the private vendors and sell them through the Stamp Department of Delhi Administration? (*Interruption*)

SHRI K. R. GANESH: The hon. Member has made a suggestion; it requires some consideration.

श्री लालजी भाई : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी अभी उन्होंने वक्तव्य में कहा है कि हम कार्यवाही करेंगे तो एक वर्ष की अवधि में सरकार के पास कितनी शिकायतें आई है ?

SHRI K. R. GANESH: This question has come to us because we supply the various State Governments the stamp papers from the Nasik Press. If any illegal transactions take place, the State Governments will have to look into them.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Higher rate of subsidy for rubber replantations to small holders

*855. SHRI A. K. GOPALAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to give a higher rate of subsidy for replantation to small holders who are unable to bear the cost involved in replanting and improving productivity of Rubber; and

(b) if so, from when?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). Enhancement of the existing rate of subsidy for replanting rubber would be considered on the basis of a cost study which is being undertaken.

Export Earnings from Shrimps

*859. SHRI B. V. NAIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the export earnings from Shrimps during the past three years;

(b) the incentives provided for the artificial culture of Shrimps; and

(c) how are the benefits of export earnings passed on to Shrimp fishermen?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) The total value of exports of shrimps during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 (April-October, 1973) was of the order of Rs. 39.82 crores, Rs. 53.21 crores and Rs. 47.51 crores respectively.

(b) No incentives are provided for the artificial culture of shrimps.

(c) Benefits of export earnings are realised by fishermen through increased prices for shrimps.

Opening of New Branches of Nationalised Banks in Rural and Tribal areas of Haryana

*860. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRI S. N. MISRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to open new branches of the Nationalised banks in the rural and tribal areas of Haryana; and

(b) if so, the names of the places selected for the purpose?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b). In pursuance of the directive of the Reserve Bank of India, all commercial banks prepare three year rolling plans of branch expansion. Banks are currently engaged in finalising their plans for the three years 1974-76. The Reserve Bank has,